The question is:

"That the debate on the Bill be adjourned *sine die*."

The motion was adopted

15.15 hrs.

Code of Civil Procedure Amendment Bill

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस विधेयक को एक बार फिर सदन के सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत कर रहा हू। जैसा कि मैं ने पहले इस विधेयक के बारे में बताया था, हमारे कोड आफ़ सिविल प्रोसीड्योर में एक धारा ८७बी है, जिस के अनुसार एक ऐसा अधिकार हमारे देश के भूतपूर्व शासकों का दिया गया है, जिस से इस देश के नागरिकों को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। मैं ने सदन के सामने कई उदाहरण रखे थे, जिन से यह साफ ज़ाहिर था कि किस प्रकार से लोगो के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा० रहा है। आज मैं सदन के सामने कुछ ऐसी मिसालें रखना चाहता हू जिन से यह पता चल जायेगा कि वास्तव में इस विधेयक पर फिर से अच्छी तरह गौर करने की ज़रूरत है। ऐसे अनेकों किस्से हैं, जिन में राजा महाराजा व्यापार में अथवा लेन देन में लगते हैं और नागरिको के जो अधिकार हैं, वे उन को बरत नहीं पाते हैं। हमारे संविधान में यह दर्ज है कि भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक के अधिकार समान हैं और न्याय की दृष्टि से भी उन को समानता दी गई है। परन्तु एक ऐसी धारा है कि जिस से यह समानता छीन ही नहीं ली गई है बल्कि इस से लोगों के विरुद्ध एक बड़ी भारी हानिकारक बात इस देश में चल रही है। इस के पूर्व कि मैं और बातें बतलाऊं, मैं दो चार उदाहरण देना चाहता हू। पिछली मर्तबा मैं ने जब इस सदन में इस विधेयक को रखा था तो हमारे विधि मंत्री श्री सेन ने कहा था कि आप बताइये कि कहां कहा मुकदमे चलाने की इजाज़त नही दी गई है और कोई भी ऐसी बात नही होगी कि जहां पर इजाज़त न दी गई हो। मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि गृह मत्रालय को आज भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी को चाहे तो इजाज़त दे सकता है और किसी को चाहे तो इजाज़त नही दे सकता है। इस सम्बन्ध में विधि मत्रालय की राय मांगी गई थी गृह मत्रालय की तरफ से या दूसरी तरह से और पूछा गया था कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिये। विधि मत्रालय ने यह कहा था कि सभी केसिस में जहां तक सम्भव हो, इजाज़त दी ही जानी चाहिये और इस इजाज़त को रोका नही जाना चाहिये। विधि मत्रालय हमारी सरकार का एक विशेषज्ञ विभाग है। उस की राय है कि मुकदमा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिये। लेकिन ऐसे उदाहरणो की यहा गिनती नही की जा सकती है जिन में इजाज़त नही दी गई क्योंकि ऐसे बहुत ही मामले हैं। कितने ही मामलो में गृह मत्रालय की तरफ से इस तरह के मुकदमे चलाने की आज्ञा नहीं दी गई है और सालो के साल गुज़र चुके हैं। जितना रुपया लोगो को राजे महाराजाओ से मिलना था, उस का बयाज भी आज तक लाखो में हो जाता, यदि उस रुपये को किसी अन्य काम में लगाने का अवसर प्राप्त हो गया होता। लेकिन लोगो को रुपया मिलता नही है। यह व्यापारिक मामलो का रुपया है। सरकार ने राजे महाराजाओ को जो अधिकार दे रखे हैं, उन के साथ मुझे कोई विरोध नही है। जब तक वे हमारे देश के शासक थे, तब तक तो उन को पूरे अधिकार प्राप्त थे और अब भी हम ने उन को एक तो जो उन के शासक होने की हैसियत से अधिकार थे वे उन को दे रखे हैं और साथ ही सब साधारण नागरिको को जो अधिकार प्राप्त हैं, उन से कहीं अधिक दूसरे अधिकार भी उन को दे रखे हैं। नागरिक की हैसियत से वे व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं डीलिंग्स करते हैं या अन्य काम करते हैं और

[श्री म० ला० द्विवेदी]

साधारण नागरिक की भांति रहते हैं तो फिर क्या कारण है कि हम हमारे साधारण नागरिकों के विरुद्ध उन को एक ऐसा स्वत्व या अधिकार दिया जाय या उन का यह अधिकार बना रहे जिस से कि दूसरे साधारण नागरिकों के जो अधिकार हैं वे छिन जायें और वे लोग अपनी गाढ़ी कमाई को वापस न पा सकें और न ही न्याय पाने के लिये अदालतों की शरण ले सकें या इस प्रकार की कोई दूसरी कार्रवाई न कर सकें ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधि के विधान में तो न्याय है लेकिन विधि मंत्रालय के विधान में न्याय नहीं है । यह बड़े आश्चर्य की बात है । यदि विधि मंत्रालय इतनी योग्यता रखता है और गृह मंत्रालय को राय दे सकता है तो क्या कारण है कि गृह मंत्रालय इस राय को नहीं मानता है ? क्यों नहीं सभी मामलो में उदारतापूर्वक नागरिकों को इजाज़तें दी जाती हैं जिस से वे अपनी गाढ़ी कमाई का रुपया प्राप्त करने के लिये न्यायालयों की शरण ले सकें, अदालतों में जा सकें ।

मैं मानता हूं कि हमारे मंत्री महोदय लोकप्रिय मंत्री हैं । किन्तु वे भी तो सभी मामलों में नहीं जा पाते हैं, सभी मामलों पर विचार नहीं कर पाते हैं । राय तो सचिवालय की तरफ से ही आती है और उस को कितने ही ऐसे मौके मिलते हैं राजे महाराजाओं के साथ काम करने के और राजे महाराजे इस तरह से वहां से अपना काम निकलवा लेते हैं । उन के पास और भी तरीके होते हैं जिस से वे अपना उल्लू सीधा करवा सकते हैं । मैं यह लांछन नहीं लगाता कि कर्मचारी भ्रष्टाचार में फंसते हैं, या किसी और बुराई में फंसते हैं । लेकिन मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन से गृह मंत्रालय में प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के कारण इजाज़तें नहीं दी जाती हैं या मनमाने ढंग से इजाज़तें दी जाती हैं । जो कोई खुश कर लेता है, उस को तो मुकदमा दायर करने की इजाज़त मिल जाती है और जो खुश नहीं कर पाता है उस को नहीं मिलती है । जो खुश नहीं कर पाता है उस के मामले में साल-दर-साल लटकते रहते हैं और इजाज़त नहीं दी जाती है । मैं आप के सामने एक मामला रखना चाहता हूं और वह भीम सेन खोसला का है । कपूरथला के महाराजा ने अपने बांड्स को बेचने के लिये उस के साथ बातचीत की और ये बांड एक लाख २५ हजार के थे और कहा कि तुम इतने रुपये मुझे दे दो और मैं कुछ दिन में कोशिश कर के बांड आप को दे दूंगा । भीम सेन खोसला ने एक लाख पच्चीस हजार रुपया उन्हें दे दिया । इसी प्रकार से महाराज ने उसे कहा कि चार हज़ार रुपये के कैश सर्टिफिकेट हैं, वे भी मैं बेचना चाहता हूं, आप रुपया दे दें और उस ने दे दिया । महाराजा ने आज तक न तो उस को बांड दिये हैं और न ही कैश सर्टिफिकेट और न ही यह रुपया उसे वापिस किया है । यह सन् १९५४ की बात है । जब इस व्यक्ति ने गृह मंत्रालय को अर्जी दी कि हमको इजाज़त दी जाये कि हम महाराजा के विरुद्ध सिविल प्रोसीडिंग्स दायर कर सकें, न्यायालय में जा सकें, तो मुझे खेदपूर्वक यह कहना पड़ता है कि इजाज़त देने में टाल मटोल होती रही और आज तक वह इजाज़त नहीं मिली है । यह उनको कह दिया जाता है कि गृह मंत्रालय ने इस पर सोच विचार किया है और वह समझता है कि इजाज़त देना मुनासिब नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि जब उसका रुपया महाराजा के ऊपर चढ़ा हुआ है, प्रमाण मौजूद है कि रुपया महाराजा ने वापस नहीं किया है तो क्या कारण है कि इजाज़त नहीं दी जाती है न्यायालय में जाने की । उल्टे उन्हें कह दिया जाता है कि समझौता कर लो, इतना रुपया ले लो, बाकी न मांगो और इसी तरह की दूसरी बातें कही जाती हैं । दूसरी तरफ मुझे विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि गृह मंत्रालय के लोगों ने प्राइवेट तौर पर

महाराजा से कहा कि तुम फिक्र मत करो, परवा मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है । इसका अर्थ यह हुआ कि चूंकि गृह मंत्रालय के पास इजाजत देने का अधिकार मौजूद है, इसलिए . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : प्राइवेट तौर पर की गई बात आपके पास किस तरह से पहुंच गई ?

Shri M. B. Thakore (Patna): There are very few hon. Members in the House. There is no quorum.

Mr. Deputy-Speaker: Why should he be so apologetic in bringing it to my notice? The bell is being rung—Now there is quorum; the hon. Member may continue.

श्री म० ला० द्विवेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि बहुत से ऐसे उदाहरण भी हैं जिन में राजे महाराजों ने व्यापार में रुपया लगाया । बहुत लेन देन किया और अन्य ऐसे कामों में उन्होंने साधारण नागरिकों का सा व्यवहार किया जिन में वे पहले नहीं करते थे । जब वे किसी देशी राज्य के शासक थे तब वह राज्य की सर्वोच्च सत्ता थे, इस लिये उन के व्यापार में आने का प्रश्न नहीं आता था, लेकिन जब वह साधारण नागरिक की हैसियत से इस तरह के व्यापारों में पाये जाते हैं । देश में उनको विशेषाधिकार दिये गये थे । दूसरे विशेषाधिकार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा । वे बने रहें, लेकिन जब वे नये किस्म की चीज में प्रवेश करते हैं, और एक साधारण नागरिक की तरह से व्यापार में आते हैं तो उन में और दूसरे नागरिकों में भेद भाव नहीं होना चाहिये । आप जानते हैं कि हमारे राजे महाराजाओं को वे अधिकार दिये गये हैं जो विदेशी राजाओं को प्राप्त हैं । अब आप बताइये कि एक देश का रहने वाला जो भारतवर्ष का नागरिक भी है, उसे विदेशी नागरिक के अधिकार दे दिये जायें तो क्या यह शोभा की बात है ? फिर भी मैं केवल एक छोटी सी बात के लिये यहां पर विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं और वह यह कि सिविल प्रोसीजर कोड की धारा ८७ बी उठा ली जाये । इस में किसी भी व्यक्ति को एक शासक के विरुद्ध, चाहे उस के द्वारा किसी किस्म का अन्याय हुआ हो, मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है । मैं चाहता हूं कि यह धारा उठा ली जाये। एक उदाहरण मैं ने आप के सामने रखा, दूसरे उदाहरण भी हमारे सामने हैं । एक उदाहरण है जावरा की रियासत का । जावरा के नवाब साहब ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपनी बेगम को दिया । उस में एक मकान और कुछ और जायदाद थी । जब उन के मरने के बाद उन का लड़का गद्दी पर बैठा तो उस ने अपनी मां का मकान और जायदाद छीन ली और अब वह उस को देना नहीं चाहता । कायदे से, कानून के मुताबिक भी वह बेगम साहब ही उस की हकदार हैं और मालिक हैं । लेकिन चूंकि मुकदमा चलाने का अधिकार किसी नागरिक को प्राप्त नहीं है इस लिये उस की विधवा मां भी इस बात का कोई उपाय नहीं पा सकती जिस से वह जायदाद उस को मिल जाय । आज उस का पति नहीं है, वह बेवा की हैसियत से है । उसके पास कोई साधन नहीं है कि वह दूसरा मकान बनवा सके और जीवन यापन का दूसरा साधन पा सके । ऐसी उसकी हालत है । अगर रियासत का शासक उसके साथ अन्याय करता है तो गृह मन्त्रालय उसको इजाजत नहीं देता है मुकदमा चलाने का । न उसकी जायदाद ही दिलाता है और न कोई इन्तजाम ही करता है । तो फिर आखिर उस का क्या होगा ? इससे यह होगा कि हम अपने नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं जो कि साधारणतया संविधान के द्वारा उनको मिल चुके हैं । यह संविधान की उपेक्षा है और उसी की एक धारा की आड़ में हमें अपने नागरिक अधिकार को खत्म कर दें यह हमें शोभा नहीं देता । मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । एक दूसरा किस्सा बिलासपुर के महाराज का है ।

[श्री म० ला० द्विवेदी]

एक बुढ़िया ने कोई ३० हजार की रकम महाराज विलासपुर के पास जमा की थी। जब वह नौजवानी में थी, उसका राज था और उसका विश्वास था कि वह उसे मिल जायगी, जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन रियासत खत्म हो गई। अब कहते हैं कि राजा बुढ़िया का रुपया नहीं देना चाहते हैं। बेवा है, बुड्ढी है, चल फिर नहीं सकती है, खाने पीने और जीवन यापन का जरिया नहीं है। राजा साहब देने से इनकार करते हैं, उसके पास इतने साधन नहीं हैं कि वह उस रुपये को प्राप्त कर सके या अपने खाने पीने का प्रबन्ध कर सके। गृह मन्त्रालय की ओर से उसको भी इजाजत नहीं मिल रही है कि वह मुकदमा चला सके और अपनी जायदाद को प्राप्त कर सके। इस किस्म के बहुत से उदाहरण मैं सदन के सामने रख सकता हूं। लेकिन मैं बहुत से उदाहरण रख कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन सदन इस बात को समझ ले कि वास्तव में जो हमारी शिकायत है वह सच्ची शिकायत है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आज हम कोई बहुत बड़ा अधिकार मांग रहे हैं। या कोई बहुत बड़े स्वत्व की मांग कर रहे हैं। आप इस को ठंडे दिल से सोचिये और इस विधेयक को स्वीकार कीजिये। मैं आपकी सूचना में यह लाना चाहता हूं कि इस विधेयक को चलते-चलते करीब साल भर हो गया है। इस पर विचार चलता ही रहा है। जब तक विधि मंत्रालय की राय नहीं थी तब तक हम से यह कहा गया कि हम इसमें राय नहीं ले पाये हैं, इस पर ठीक तरह से विचार नहीं हो पाया है, और इस कारण यह मुल्तवी होता गया। एक समय किसी और कारण के इस विधेयक पर विचार इस सदन में मुल्तवी हो गया और आज बहुत दिनों के बाद फिर आया है। मैं सोचता था कि हमारे मंत्री जी इस विषय में काफी सोच विचार कर चुके होंगे। लेकिन गृह मन्त्रालय के मंत्री श्री दातार ने बतलाया कि वह अभी इस मामले में तैयार नहीं हैं और वह मेरा बिल अभी देख नहीं पाये हैं। इस कारण वह इस मामले में अभी कुछ नहीं कह सकते। आज हमारे विधि मंत्रालय के उपमंत्री कहते हैं कि वे इस बात से राजी हैं और इस बात को गहराई से और अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन उनके सामने कुछ कठिनाइयां हैं और वे ऐसी हैं कि सेक्रेटेरियेट की तरफ से नोट आ जाता है तैयार होकर, जिसे ब्रीफ कह सकते हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह बातें आप क्यों कहते हैं। यह उन को ही कहने दीजिये जब उनका समय आये। आप उनकी कठिनाइयों की चर्चा क्यों करने हैं?

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं इस लिये कह रहा हूं कि सबको पता चल जाय और मैं चाहता हूं कि सदन समझ ले कि असलियत क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह आपको नहीं कहना चाहिये, यह उन्होंने आपको विश्वास में लेकर कहा है।

श्री म० ला० द्विवेदी : उन्होंने तो नहीं कहा है, लेकिन मुझे मालूम हो गया है। वे..

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात तो उन्हीं के बारे में है भेद किसी ने भी दिया हो।

श्री म० ला० द्विवेदी : सदन के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे भेद की बातें यहां लायें और सरकार को ठीक तरह से चलाने का प्रयत्न करें। यह हमारे स्वत्व की बात है कि हम कहां से पता लगाते हैं और अपने देश की जनता और देश के नागरिकों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में आप को इससे प्रसन्न होना चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय। यह कार्य सरकार का है कि वह जांच करे और अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा दे, लेकिन सभी बातों पर टाल मटोल करना उचित नहीं है। न्याय की बातों पर हमारी सरकार को जल्दी विचार करना

चाहिये क्योंकि हम ने इस देश में बार बार कहा है कि हम एक समाजवादी ढांचा स्थापित करना चाहते हैं, हम ने बार बार कहा है कि हम नागरिकों को बराबरी के अधिकार देना चाहते हैं। हमने बार बार कहा है कि हम एक ऊंचे किस्म की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। मैं यह बात बारम्बार कहना चाहता हूं कि बारम्बार इस विषय को सदन में लाये जाने पर भी, और इस बात का खुलासा होने पर भी इसमें टाल मटोल की जा रही है और इस सम्बन्ध में उचित निर्णय नहीं लिया जा रहा है। आज समय आ गया है कि इस पर अच्छी तरह से गौर किया जाय और इस मसले को टाला न जाय। हमें यह विश्वास अगर हो सके कि लोगों को न्याय मिलेगा तो कोई आपत्ति नहीं, जैसा है कानून वैसा ही बना रहे। हमें इस बात पर भी कोई आपत्ति नहीं है कि जो अधिकार गृह मन्त्रालय के पास है जो कि इस को डील करता है, कि इजाजत दी जाय या नहीं, वह उस के पास रहे यदि यह अधिकार कोर्ट के पास पहुंच जाय कि वह परमिशन दे कि मुकदमा दायर किया जा सकता है या नहीं। कोई भी इजलास इस को तय करे तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि न्यायालय में जाकर कम से कम न्याय तो हो सकेगा। मुझे इस बात पर आपत्ति नहीं है कि हमारे शासकों के अधिकार बने रहें, क्योंकि बहुत से शासक तो बड़े अच्छे हैं और हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, वह किसी का भी रुपया वापस कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे शिकायत उन से है। सबसे नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की है कि यह अधिकार कम से कम न्यायालयों को दे दिया जाय कि जो दुखी आदमी हैं, जिसका रुपया नहीं मिल सका है अगर वह न्यायालय को अर्जी दे कि उसको मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी जाय तो न्यायालय उस की जांच पड़ताल कर के फैसला करे। मुझे आशा है कि इस प्रकार सब को न्याय मिल सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से अपील करता हूं कि वह इस विधेयक को स्वीकार करे।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908, be taken into consideration."

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो पेश हुआ है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। हमने निश्चित रूप से इस देश में एक समाजवादी व्यवस्था से सम्बद्ध सरकार स्थापित करने का संकल्प किया है और इस दिशा में यह देश प्रगति भी कर रहा है। जब राजकीय व्यवस्था भंग की गई इस देश में तब कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिन के कारण हमने राजाओं को कुछ सहूलियतें इसलिये दी कि वे अनिवार्य लिटिगेशन में न उलझ जायें। विधि मंत्रालय पर इस बात का अधिकार रक्खा जरूर गया है कि वह यह निर्णय करे कि अब किसी राजा के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई हो सकती है या नहीं। लेकिन इस प्रगतिशील राज्य के अन्दर मैं नहीं समझता कि बहुत अधिक देर तक इस तरह के संरक्षण को कायम रखना चाहिये। इस देश के अन्दर जो भी आदमी रहते हैं उनमें हम किसी किस्म के भेदभाव को बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि चाहे कोई राजा महाराजा हो या कोई इस देश का नागरिक हो सब कानून की दृष्टि में बराबर होने चाहियें। इस देश में किसी किस्म के भेदभाव की बात न रहे। इसके लिये जरूरी है कि किसी भी तबके को विशेषाधिकार या विशेष प्रकार के संरक्षण न दिये जायें, कम से कम सहजोर तबके को तो न दिये जायें। अगर कोई कमजोर तबका है तो उसको संरक्षण दिया जा सकता है लेकिन राजे महाराजे तो कमजोर तबके में नहीं हैं। उनकी स्थिति तो हमारे देश के कोटि कोटि मानव समाज से बहुत अच्छी है। ऐसी स्थिति में मैं यह नहीं समझ सकता कि

[पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी]

अगर कोई उस तबके में से गलती करे तो वह उसके लिये कोर्ट के सामने क्यों न जाये, ऐसी व्यवस्था हमारे कानून में क्यों हो। जो क्लास उन्हें वह संरक्षण दे रहा है उस क्लास को मैं आज के प्रगतिशील देश की स्थिति में अनुपयुक्त और अनावश्यक समझता हूं। हमारे साथी ने सदन के सामने जो वाकयात पेश किये वे हमारे हृदय पर चोट पहुंचाने वाले हैं। विधि मंत्रालय में और और कहीं भी लोग कुंडली मारे बैठे रहें और राजा महाराजाओं को अनावश्यक प्रोटेक्शन दें यह हमारे शासन के ऊपर एक बड़ी कड़ी टीका है। मैं समझता हूं कि शासकों को इस विषय में सजग होना चाहिये कि हमारे सेक्रेटेरियट के आदमी इस तरह के अनावश्यक प्रोटेक्शन न दें। यह जो विधेयक के रूप में संशोधन पेश किया गया है मैं इसे बहुत मौजूं समझता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

Shri Jaipal Singh (Ranchi West—Reserved—Sch. Tribes): I am sorry I was not here to listen to the earlier arguments of my very hon. friend. I oppose this Bill for one very obvious reason, and it is something which, to my mind, is very very important for India as a country, and it is that we must be men of our word for the country. We sometimes forget—we are beginning to forget—that we have 500 people to thank for the easy passage of independence and all that followed therefrom. I know we talk glibly about a socialist pattern of society. It may be an ideal. But, I have often felt that perhaps we talk more than destroy the myths that are obstructing the realisation of this ideal of ours. In the Constitution itself, we have an article whereby untouchability is abolished. I wish my hon. friend and others who feel so strongly about the rule of law, of everyone being equal in law, could exert themselves more towards the real abolition of untouchability.

I am not here to defend the rulers and the particular privilege under the law which they continue to enjoy. They themselves, if I might use an expression which is not Oxford English, have self-immolated themselves. But for them, today, perhaps India might not have been independent. We gave them our word at a time when things were difficult. They themselves realise the fact that although we gave them our word, the situation cannot continue for ever. A great deal of this irritation arises from the fact, whether my friends on the other side admit or not, that the rulers, not all of them, have been reading the writing on the wall. Some of them have been resisting certain political parties. I know it in my own area. A ruler is a good man if he is with the ruling party. Let him enjoy all the privileges that have been accorded to him. But, if he does not belong to the ruling party, he is a bad man. His wings must be clipped, his privy purse must be reduced and he must be demolished.

I think this is unwise thinking. I wonder whether if the great Sardar Vallabhbhai Patel had been sitting there, my hon. friend would have dared to introduce this Bill. My hon. friend is a man of courage, I accept that. He means well. But, I cannot help feeling that he is misguided. Is this problem important enough? Is it big enough? Does it really matter? It is a question of 500 people roughly. Out of the 500, most of them are crossing the floor, if I may say so. I speak with a certain amount of knowledge of the people concerned. I found, only last week-end, Members of Parliament visited Ajmer. We had in this company my hon. friends there who would willingly agree with my friends there. It is a peculiar alliance. My friends there would agree to anything that is for destruction. I have said so before and I repeat it again. This is a country where we value history, history that has a

meaning in the present context, history that is not standing in the way of our progress. I ask, are the rulers, today, really trying to take advantage of this particular legal privilege they have been given? I think they are the first people who will come forward and say, all right, we do not want any. I feel that in this country, in the Constitution itself, everybody is not equal. There are certain sections of the community which have special privileges. I have been more than once grossly misunderstood by the Treasury Benches when I have pleaded for something very very special for India's most ancient millions, the Adivasis. It is not that I think that the Adivasis should be above law. It is not because of that. If you are going to have a socialist pattern of society, the fundamental thing that my hon. friend and his supporters should appreciate is the fact that in a democratic society, democracy will flourish only if you accept the fact that the minority of one shall be heard. Is that the situation today? Can we honestly say that? Until we ourselves destroy the deep-rooted myths and then talk of democracy, I feel we do not know the meaning of equality. Equality does not mean uniformity. It is a question of unity in diversity. In this particular case, as far as this Bill is concerned, I feel it is a vindictive measure.

This Bill would not have been brought forward but for the fact that these 300 people disagreed.

Shri M. L. Dwivedi: Question.

Shri Jaipal Singh: Not all of them: quite a few of them have become very good rulers because they have joined the ruling party. The evidence is there in this very House. But, some of them, may be most of them, have certainly woken up to the fact that they have ceased to be rulers. Mr. Deputy-Speaker, I do not understand why this expression 'ruler' is there, because they are no longer rulers. That is the very first thing. I do not know why the expression 'ruler' is used at all.

Mr. Deputy-Speaker: Because we agreed that we would continue to call them Rulers.

Shri Jaipal Singh: If we have agreed, if we have agreed firmly, it is shere impertinence on the part of any hon. Member of this Parliament to introduce a Bill of this nature, if we have firmly agreed, as you have said.

Shri M. L. Dwivedi: Does he mean to say that this Parliament is not competent to revise its judgment at any time?

Mr. Deputy-Speaker: Not at all.

Shri Jaipal Singh: Parliament can always become wiser. But I say, my hon. friend, I think I can say, my Rt. hon. friend—I hope one day he will occupy the Benches over there, I hope he will succeed the great Sardar Patel who was a man of his word...

Shri M. L. Dwivedi: My hon. friend has not understood that it does not want to take away that which Sardar Patel has guaranteed to all the rulers. It is only private transactions which were not guaranteed to the rulers.

Shri Jaipal Singh: I am very very surprised that an old Parliamentarian like my hon. friend is trying to draw a distinction between a private deal—I do not know where the private deal was. This is in the statute. How can anything be in the statute and be a private deal, I do not understand. I must be forgiven if I speak forthright. I know my hon. friend over there, Shri H. N Mukerjee is there. Well, I do not wish to give out any secrets. But I want to tell my friend there, and everybody else in this House that India will be the poorer for the grandeur that is associated with the rulers. I do not quite know why the word

[Shri Jaipal Singh]

'ruler' is still there. As long as you have given them the word, you have to respect that. We should be men of our word After all, it is a question of one's life time.

Sir, we talk of Privy Purses and the like May I know why hon. Members of Parliament themselves ask for certain privileges? Why are they not on level terms with the rest of the communities in this country? Sir, I need not go further I am not a lawyer I do not wish to argue these things, but I do feel that we are big enough and we can manage to forget these five hundred rulers and we can get on without these five hundred rulers But, let them have these privileges, if we have given them our word Certainly, I am not saying that for ever eternally we have to continue this privilege But the thought behind it, the motive behind it, the purpose behind it, is mean I heartily oppose this Bill

Mr Deputy-Speaker: Shri M B Thakore.

Shri M. B Thakore. Mr Deputy-Speaker, Sir,

Mr. Deputy-Speaker: Now some other hon Members have made up their minds to speak So, every hon Member shall be brief.

Shri M. L. Dwivedi: Time may be extended by half an hour.

Mr. Deputy-Speaker: Just now he is putting the proposal. We took this up at 3 O' clock and the hon. Member did not say this at that time We will see how it proceeds.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): I should like to interrupt for about five minutes.

An Hon Member: For about five minutes only.

Shri Datar: We come in so far as permission is concerned. My hon friend will deal with the rest. Therefore I would like to intervene for about five minutes.

Mr. Deputy-Speaker: All right. Shri M. B Thakore may continue

Shri M. B. Thakore: I congratulate Shri Dwivedi for introducing a measure like this. I fully support him In this measure he excludes the State of Jammu and Kashmir. Now, all our leaders say that Jammu and Kashmir is part and parcel of India. The representative of the State of Jammu and Kashmir has stated in this very House that it is part and parcel of India and part and parcel of the Indian Union Why should there be any distinction? So I oppose such provision in the Bill.

The second observation that I want to make is on the immunity of the former rulers as far as the Civil Procedure Code is concerned These immunities started from former times. The British Government recognised the sovereignty of all the States. Now they are no longer Sovereign States. These rulers are as equal as any citizen of India. Moreover, Sir, we have adopted a democratic Constitution where equality before law is recognised and in courts of law this is proclaimed My learned friend Shri Jaipal Singh said that equality before law does not apply to the former rulers in respet of such immunity from the Civil Courts. I do not agree with that. The immunity was recognised by the foreign power, the British Government, on the ground that they were sovereign States under the British suzerainty. One thing I want to add, and that is, that it does not apply to the present rulers but it inherits which is much more dangerous. It will inherit to their descendents irrespective of what they do and what they would do in future. So, it is against the fundamental rights conferred by our sacred Constitution.

We have adopted a socialist pattern of society. Many of our former rulers served as Governors. They also talked about the socialistic pattern of society. I do not think that they could say that they must have some privilege of this type.

Sir, I know that Members of Parliament who are elected under our Constitution are also not immune from the Civil Procedure Code. I do not understand why the Home Ministry or our Government is lying idle not to apply the same kind of disqualification to the former kings and maharajas.

श्री पद्म देव (चम्बा) : उपाध्यक्ष महोदय, १५ अगस्त १९४७ की रात के १२ बजे से पहले हिन्दुस्तान के ५६३ राज्य थे। उस के बाद ५६२ राज्य यहा रहे। यह ख्याल करते हुए कि वे भी अपनी परम्परा को कायम रखेंगे, भारत सरकार ने उन को सब प्रकार की सुरक्षा दी, महल, जेब खर्च, जागीरे वगैरह वगैरह दी। उस के लिये मै समझता हू कि किसी को भी उसै वक्त कोई ज्यादा अफसोस नही हुआ था। किन्तु उस के पश्चात् हम ने अपना कांस्टीट्यूशन बनाया और तब प्रश्न उठा कि जिन लोगों के लिये भारत सरकार के कोष से करोड़ो रुपया जाता है, उन को भी इलैक्शन में खड़े होने का अधिकार मिलना चाहिये या नही। निश्चय हुआ कि वे भी दूसरे नागरिको की भांति भारत के नागरिक है। अन्य नागरिकों की भांति उन को भी इन सब मामलों में समानता का अधिकार मिला हुआ है। उस के पश्चात् हमारे यहां के ५६२ भूतपूर्व राजाओं ने अपनी पूंजी बढ़ाने के लिये व्यापार में, नौकरियों में तथा दूसरे क्षेत्रों में भाग लेना शुरू किया और राजकीय पुराना ठाठ बाठ सब का सब छोड़ दिया। इस के बारे में मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यही कहना चाहता हूं कि यह सब दुरुस्त ही था कि जब सब एक ही सतह पर है, एक तरह के नागरिक हैं, तो कोई कारण नहीं कि बिना किसी लाइसेंस के असमित शस्त्रास्त्र उन के पास रहें या दूसरी चीजें रहें या जागीरों से थोड़ा सा रुपया मिले, इलैक्शन लड़ने के लिये देश का उसी तरह से खर्च हो, ये सब ऐसी चीजें है जिन पर विचार होना चाहिये।

मेरे एक माननीय मित्र ने कहा है कि अगर सरदार पटेल होते तो उन के सामने किसी की जुर्रत न होती कि इस किस्म का बिल ला सके। मेरा विश्वास है कि अगर सरदार पटेल जिन्दा होते तो शायद इस किस्म की बहुत सारी चीजें न होती और पुराने निशान कभी के मिट गये होते और जो अशान्ति करने वाली और लोगो मे असन्तोष पैदा करने वाली बातें है, वे भी कभी की खत्म हो गई होती। लेकिन वह तो भूत की बात है, आज की नही है।

16 hrs.

मुझे अफसोस है कि एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि दुश्मनी की वजह से इस विधेयक को लाया गया है। यह भी कहा गया कि बेचारे रूलर्स को जीने का अधिकार तो रहना ही चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि यहा जागीरे छीनने का सवाल तो नहीं है। यहां पर तो सवाल यह है कि जब वे साधारण नागरिको के साथ रहते हैं, कारोबार करते हैं, व्यापार में हिस्सा लेते हैं और अन्य प्रकार का लेनदेन करते हैं तो अगर कल कोई इस तरह की बात हो जाती है कि किसी को पैसा नहीं मिलता या कोई और गलती वे करते हैं, तो उन के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार तो साधारण नागरिकों को मिलना ही चाहिये। मेरा यह पूरा विश्वास है और न्याय इस बात की मांग भी करता है कि जो देश का कानून है वह तो सब के लिये बराबर ही होना

[श्री पद्म देव]

चाहिये । आप चाहें तो राजाओं को जो खर्चा इस वक्त दे रहे हैं, उस से और अधिक दे दें, महल दे दें, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स जो बन रही हैं, या बन गई हैं, उन में से उन को कोई बिल्डिंग्स दे दें जिन के पास नहीं हैं, लेकिन जहां तक कानून का ताल्लुक है वह सब के लिये समान होना चाहिये । जब वे लोगों के साथ रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो कोई भूलें, कोई गलतियां भी कर सकते हैं और उन भूलों और गलतियों के लिये जो न्यायालय है वह सब की पहुंच में होना चाहिये, जो चाहे न्यायालय में किसी के विरुद्ध शिकायत ले कर जा सकता है, इस की इजाजत होनी चाहिये । हर एक को अपने अपने कष्ट, दुख, तकलीफ हर एक व्यक्ति के विरुद्ध जोकि दोषाधिकारी हो, न्यायालय में ले जाने का पूरा अधिकार होना चाहिये ।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय म० ला० द्विवेदी जी ने जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही सामयिक है, बहुत ही जरूरी है और देश के हित में है, इसलिये उसे अवश्यमेव स्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री जयपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं । मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि न्यायालय के सामने सब बराबर न हों । मेरे कहने का मतलब केवल इतना था कि इन लोगों की गिनती कोई ज्यादा नहीं है और जो जबान उन को दी गई है, जो अधिकार एक बार दिये गये हैं, उन को हमें कायम रखना चाहिये, अपनी जबान पर कायम रहना चाहिये ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक यहां पर रखा गया है, इस पर बहुत ज्यादा वाद विवाद की आवश्यकता मालूम नहीं देती है । मेरे विचार में इस विधेयक का रूप अगर थोड़ा सा बदला हुआ होता, तो वाद विवाद की नौबत ही न आती । मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इस में कुछ सुधार कर के इस को स्वीकार कर लेगी ।

जो धारा ८७(बी) है उसको इस विधेयक की रू से निकाल देने से जो कुछ दिक्कत होंगी, उन को तो मेरे भाई जयपाल सिंह जी ने आप के सामने रख दिया है । उन्हों ने ठीक ही कहा है कि इस का मतलब दिये गये वादों से पीछे जाना होगा । वादा तो दे दिया गया, वह कब तक चालू रहे यह सोचने की बात अवश्य है । साथ ही साथ जो वादा देने वाला था जब वह जिन्दा था शायद उसी के समय में दफा ८७(बी) भी बनी थी । इस वास्ते जब वह बनी तो खूब समझ बूझ कर ही बनी थी । चन्द सूरतों में ही उन को राहत दी गई थी और यह कहा गया था कि आम तौर पर उन को अदालतों में घसीटा न जाय और जब तक केन्द्रीय सरकार समझ न ले कि उन का अदालतों के सामने जाना जरूरी है तब तक उन को अदालतों में न ले जाया जाय ।

माननीय म० ला० द्विवेदी जी ने जो कारण अपने विधेयक को उपस्थित करते समय बतायें हैं, उस में उन्हों ने कहा है कि मूल कारण यह है कि आज कल बहुत से दावे राजाओं के खिलाफ लोग करना चाहते हैं । उन्हों ने कहा है कि साधारण नागरिक की हैसियत से अगर कोई राजा तिजारत करता है, पैसे का लेन देन करता है, ऐसी अवस्था में अगर उस को किसी राजा के खिलाफ दावा करना पड़े, तो बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं, रास्ते में बहुत सी रुकावटें पेश आती हैं, इसलिये जो नियम है, इस को बदल दिया जाना चाहिये और यह जो बाधा

है, इस को निकाल दिया जाना चाहिये ताकि आम नागरिक की तरफ के किसी राजा महाराजा के खिलाफ दावा हो सके । उन की यह बात तो सही प्रतीत होती है अपनी जगह पर । लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ के उन को यह आश्वासन मिला हुआ है कि उन के कुछ प्रिवलेजिस हैं, जिन को छीना नहीं जायगा । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दफा ८६ के अन्दर यह साफ लिखा हुआ है कि जहां कहीं तिजारत की बात हो, वहां पर परमिशन दे दी जायेगी । उस में कहा गया है कि इन हालात को छोड़ कर बाकियों में परमिशन नहीं दी जायगी । दफा ८६ की सब क्लाज के भाग (बी) में लिखा है :—

"by himself or another, trades within the legal limits of the jurisdiction of the Court"

ऐसी अवस्था में केन्द्रीय सरकार परमिशन दे सकती है ।

श्री अ० ला० त्रिवेदी : नहीं दी जा रही है, यही तो शिकायत है ।

श्री सिन्हा : अगर दी नहीं जा रही है, तो यह देखना तो इस समय केन्द्रीय सरकार का काम है । लेकिन उसे इन हालात में परमिशन देनी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि जहां पर रूलर्स ने अपने अधिकारों को स्वतः ही छोड़ दिया है प्रकट रूप में या किसी और रूप में, वहां पर तो इजाजत न मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है । मैं उम्मीद करूंगा कि जब सारा राज्य उन का चला गया, शासन चला गया, तो इस एक छोटे से अधिकार के लिये वे बहुत ज्यादा लालायित भी नहीं होंगे और समझ जावेंगे कि वे खुद ही इस अधिकार को भी छोड़ देंवे । वहां पर वे साधारण नागरिक के जैसे बैठे हुए हैं, कोई ज्यादा प्रिवेलेज भी उन के नहीं हैं, तो फिर कोर्ट के सामने भी वे कोई प्रिवेलेज नहीं चाहेंगे । लेकिन यह थोड़ा सा डर रहता है कि प्रतिशोध की भावना भी आ सकती है और उस के लिये थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहना चाहिये । और उस प्रोटेक्शन की आड़ में उन को सुविधायें मिली हुई हैं ।

मैं समझता हूं कि अगर इस बिल को गवर्नमेंट इस तरह से बदल दे तो यह अच्छा रहेगा । यहां पर जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का शब्द आया है दफा ८६ सब क्लाज २ के अन्दर, उस की जगह पर कोर्ट कर दिया जाना चाहिये । इस के बाद इस को इस तरह से पढ़ा जायगा :—

".....in case of any suit or class of suits, the Court in which the Ruler may be sued, but it shall not be given, unless it appears to the Court that the Ruler....."

कोर्ट के सामने डिसक्रिशन हो कि अगर वह समझे कि ऐसे मामलों में दावा हो सकता है अदालत के अन्दर और मामला तिजारत का है तो वह उस को दायर करने की इजाजत दे दे । इस का मतलब यह होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आने में जो दिक्कत होती है, अधिक खर्चा होता है, वह खत्म हो जायगा । अब साधारण नागरिक दावा दाखिल करेगा और साथ ही साथ परमिशन के लिये भी दरख्वास्त देगा और बतायेगा कि दावा इस नेचर का है कि अदालत में जा सकता है, फिर अदालत चाहे तो इस की इजाजत दे दे और चाहे तो न दे । तो दफा ८७ बी का क्लाज अगर छोड़ दिया जाय और आइन्दा के लिये अदालत को यह अधिकार दे दिया जाय, जहां पर कि आपने भूतपूर्व शासकों का सवाल रखा है, तो मैं समझता हूं कि ठीक रहेगा । औरों के लिये तो आपने दफा ८५ और ८६ रखा है लेकिन दफा ८७ के द्वारा हमने अपने पुराने राजाओं को कुछ अधिकार दिया है । तो या तो आप दफा ८७ बी को हटा दें या फिर उस को अमेंड

[श्री सिंहासन सिंह]

कर दें। जहां पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट शब्द आये हैं उन की जगह पर आप "कोर्ट" कर दें तो कोई हानि नहीं है। ऐसा कर देने से शायद हमारे द्विवेदी जी का मतलब भी हल हो जायेगा और दूसरों की दिक्कतें भी हल हो जायेंगी। हमारे बारे में भी कोई गड़बड़ी नहीं पड़ेगी और वह ज्यों का त्यों सही रास्ते पर चलता रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करूंगा कि वह बिल जल्दी से जल्दी पेश कर दे या इस में ही किसी संशोधन को मान ले ताकि यह चीज हो जाय और हर एक नागरिक समझे कि जहां तक व्यवहार का सम्बन्ध है उस में पुराने राजा और वह एक हैसियत के हैं। और बातें कानून में रही आयें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

Shri Ajit Singh Sarhadi (Ludhiana): The Bill under discussion is certainly a very simple one, and proposes an amendment which is intended to eliminate the privilege of a particular class, but the principle involved is a very important one, and that principle is whether that particular class whose privilege is being taken away had received any commitment or any understanding previously. I agree with my hon. friend from Ranchi that certainly if there has been a commitment or understanding or an assurance, then that must be honoured, but my feeling is that the Constitution does not contain any assurance or any provisions of the kind.

The only article that governs this is article 362 which lays down:

> "In the exercise of the power of Parliament or of the Legislature of a State to make laws or in the exercise of the executive power of the Union or of a State, due regard shall be had to the guarantee or assurance given under any such covenant or agreement as is referred to in article 291 with respect to the personal rights, privileges and dignities of the Ruler of an Indian State."

The only guarantee which the Constitution provides—and I understand that this provision is based on a certain understanding that was arrived at—pertains to what is contained in article 291. You will see that article 291 discusses those items and says:

> "Where under any covenant or agreement entered into by the Ruler of any Indian State before the commencement of this Constitution, the payment of any sums, free of tax, has been guaranteed or assured by the Government of the Dominion of India to any Ruler of such State as privy purse—
>
> (a) such sums shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of India; and
>
> (b) the sums so paid to any Ruler shall be exempt from all taxes on income.".

We have got to see whether in the light of these provisions in the Constitution which guarantee certain privileges pertaining to the income or the privy purses of the Rulers and to income-tax on certain incomes, this Bill in any way infringes these privileges. If it infringes, then it will be an amendment of the Constitution as such, and we cannot amend it unless we follow a certain procedure. If it does not infringe, then it is a perfectly legitimate proposal or amendment which must be considered on its own merits.

From that point of view, we have got to see whether on merits, this amendment is just and expedient or not. The hon. Mover of this Bill has given certain reasons in support of his proposals. It cannot be denied that the princes or the Rulers are entering

into commercial transactions, are entering into business and are dealing with private people. If that is so,—and that is an apparent fact—then, that this clause should remain and that the party concerned should approach the Central Government for sanction before he can take his case to the forum of a court of law for proceeding against the Ruler, would, I think, be unfair; it would not only be against the basic principle in article 14 which lays down equality before law, but it would be unjust to the individual who wants to proceed against him, because it puts him under a handicap. And I would respectfully submit that it would not be in the interests of the princes themselves. I do not think that with all the sacrifices that they have made for the consolidation of the country, with all the patriotism they have shown, they want to remain as a class above the people, and different from the people. I think they also desire equally that there should be an integration and there should be equality. And in a matter of this type, their dignity, their right, and their privilege lie in this that there should be equality before law. If the Constitution does not provide it—here, it is for the Law Minister to clarify the position; my reading of the situation may be wrong—I do not think it would be fair and just that section 87B of the Civil Procedure Code should remain; therefore, the amendment that is proposed should certainly be accepted. It would not only be just, as I said, but it would also be expedient, expedient in the sense that the Central Government would not be burdened with all the applications to it for permission. I quite see that the Central Government would not be in a position to refuse where an individual comes before them for permission, who has got some grievance of a civil nature against a Ruler; they would be bound to give permission in all fairness and justice to that individual who approaches them. But all the same this will lighten their work. The courts are there, and the courts should be the forum for justice between all the people.

Therefore, I would submit respectfully that taking an overall picture of the objective which we want, namely a socialistic pattern of society or—the socialistic pattern of society is not so very relevant—the creation of a classless society in India, and a sort of welfare State in our country, I do not think that we need have a privileged class, unless, of course, the privileges are given by the Constitution.

With these words, therefore, I support Shri M. L. Dwivedi's Bill. There is just only one thing more, and that is that it has been suggested that the courts should be the forum to decide on each application whether permission should be given. That, to my mind, is not fair at all. The question is whether the individual should have a right to seek a certain remedy that the Civil Procedure Code gives him. If he has got that right he should have the right to approach the court of law which has got the jurisdiction.

As regards the personal appearance of the princes, if necessary, they may be exempted from personal appearance, just as has been provided in the Criminal Procedure Code. That provision can be made. The court may not even call them for their personal statement either; the statement can be made by the agent.

Shri Jaipal Singh: Why not?

Shri Ajit Singh Sarhadi: I do not think that the princes or these Rulers themselves would like that these privileges should remain and they should be a class different from the people. I think the time has come when with all the guarantees, with all the commitments, and the assurances, and the understandings that they have and that should be honoured, as for the rest of the things, there should be equality. With these words, I support Shri M. L. Dwivedi's Bill.

Shri P. K. Deo (Kalahandi): I do not hold any brief for any Ruler or

[Shri P. K. Deo]

any particular class, but I would like to speak, and examine this legislation from the viewpoint of a citizen of India. Though the provisions are incompatible to our present ideology of a democratic and a socialistic pattern of society, at the same time, I feel that we are wasting much time in discussing a legislation which is obsolete in practice, and which has been hardly used. I do not think any Ruler would be coming forward to seek protection under this piece of legislation; and invariably, in every case, when permission is being sought for, it is readily granted by the Government unless the legislation is vindictive.

I feel that this is not the way to do the things. It would have been much wiser if the Rulers could have been addressed by Government to withdraw their privilege or to surrender this privilege; then it would have been much nicer I do not know how far we would be competent to bring forward a legislation of this type, especially when these safeguards have been provided in article 362 of the Constitution which guarantees the continuance of certain privileges of the Rulers, which they have been enjoying since some time. This provision was made against vindictive litigation. This provision is a very old provision and was there even before Independence came to India. This was a creation of the then Central Government, and this has been continued. The continuance of this privilege has been guaranteed under article 362 of the Constitution which says in clear terms that

> "In the exercise of the power of Parliament or of the Legislature of a State to make laws or in the exercise of the executive power of the Union or of a State, due regard shall be had to the guarantee or assurance given under any such covenant or agreement as is referred to in article 291 with respect to the personal rights, privileges and dignities of the Ruler of an Indian State."

In this connection, I would like to point that if Government are really serious that there should be no distinction between different classes of persons in this country, they should actually carry out their policy in a more dignified way; and they should seek the co-operation of the persons concerned in this regard.

I would like to submit that if we go on violating our sacred words and promises, it will carry a very bad impression especially to our critics that these people who made promises or who entered into any sort of agreement or covenant etc. start breaking them the next day; that sort of misunderstanding and misapprehension should be cleared.

Therefore, I request the hon. Mover of the Bill to withdraw his Bill, because if he is really serious that this distinction should go, then the proper way would be to request the Rulers, so that they would surrender these privileges in the greater interests of the country.

Shri Jaipal Singh: May I just make one clarification? I would not take more than sixty seconds. It might appear to hon Members as though I was holding a brief for the Rulers.

I was merely trying to focus the attention of hon. Members on the fact that there is no absolute equality given in the Constitution. I as an Adivasi have much better privileges than my hon. friend there, and I shall fight to the last inch to see that the word given to me and my people shall continue and shall be honoured.

Let us go to the fundamental privileges. Take, for example, the question of freedom of movement. If you are going to have absolute freedom of movement in the tribal areas, you are going to lose a very big chunk.

Let me tell you this. The time may come when these special safeguards will be surrendered by the people

themselves But this is not the occasion for that.

The same thing in regard to the question of property—the right to buy and sell You know that an Adivasi cannot sell his land to anybody and everybody.

Mr. Deputy-Speaker: 60 seconds might be exceeded now!

Shri Jaipal Singh: I have only used 25 seconds; I still have 35

I would like my hon friend to look at page 23 of the Annual Report of the Ministry of Home Affairs where even the word 'Ruler' has taken a peculiar complexion Even a jagirdar has become a Ruler I do not quite know

Mr. Deputy-Speaker: Taking up other points would mean a fresh speech

Shri Jaipal Singh: I am not here defending the Rulers The Rulers can defend themselves By their conduct and example, they have set an example to the rest of the country They have, as I said earlier, self-immolated themselves, and I wish the rest of us would learn a lesson from them

Shri Panigrahi (Puri) I rise to support the Bill which has been brought forward by Shri M L Dwivedi The Bill is timely Let Government accept this Bill and let them come forward to abolish further special privileges which are being given and being continued to the ex-Rulers of India

The arguments boil down to two points. The first is whether according to article 14 of the Constitution, the right of equality has been given to every citizen in India and whether the Rulers were considered as a specially privileged class so that they could be exempted from the scope of article 14. Secondly, at the time of the merger of the Indian States with the rest of India, there was an agreement with the Rulers. Are Government going to continue to abide by those agreements with the Rulers? My hon. friend, Shri Ajit Singh Sarhadi, quoted article 362 of the Constitution I perfectly agree with him Article 362 only deals with the special privileges to the Rulers as given under article 291 It says:

> "In the exercise of the power of Parliament or of the Legislature of a State to make laws or in the exercise of the executive power of the Union or of a State, due regard shall be had to the guarantee or assurance given under any such covenant or agreement as is referred to in article 291 "

Mr Deputy-Speaker: Article 291 only refers to one condition in the covenant There are other conditions and guarantees also This is not the only covenant that was entered into, that privy-purse shall be there There are others about title, status, dignity and so on All those things are there

Shri Panigrahi: I am coming to that. As far as I know when the question of amending the Constitution of India comes in, a different procedure has to be adopted That is what the argument comes to

There are further agreements with the ex-rulers But so far as this privilege of being treated as a special citizen is concerned, I say, it goes against the constitution of India.

If we read article 291 we will see that there are other agreements than the question of special privilege of the privy purse Article 291 will be considered as going against the fundamental rights, guaranteed under article 14 to a citizen of India. So, I submit that this Bill moved by my hon. friend Shri Dwivedi is very timely and the Government of India should really take it into serious consideration. When the ex-rulers of India are

[Shri Panigrahi]

taking part in all kinds of political activities and they hope also to rule some part of the country, it is better that whatever special privileges are there should be taken away from them.

These special privileges were given at a time when the internal situation and the security position of India was difficult, say in the years 1946 and 1947, and we should see whether that position still continues today in the year 1969. These questions have to be viewed from two angles, the question of equality of law and the question of equality of rights for every citizen of India. Secondly, if the Government of India agreed to any such special privileges at a time when India was passing through a very difficult crisis, whether those special conditions prevail today in the country so that these special privileges should be continued for years to come.

I think the times have changed and there is a great demand in the different States of India even to allow Rs. 5½ crores as privy purse to these ex-rulers and again to give them special privileges. I earnestly request that Government should take into consideration the feeling of the people all over the country—and especially in my State of Orissa—and should try to remove all the special privileges that are being given to the ex-rulers of India.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister.

Shri Karni Singhji (Bikaner): I would like to say a few words, Sir

Mr. Deputy-Speaker: Yes; certainly

Shri Karni Singhji: Sir, for eight years I have had the honour to represent the people of India in this House and, I have never said a word about the Princes and neither do I belong to that old order; in this House, neither do I represent them. Since my hon. friend discussed this question once with me in the lobbies, I thought I might perhaps be able to put forward the reasons why this particular exemption or privilege was given.

What might have inspired Sardar Patel was to protect the rulers from a certain amount of victimisation that was likely to take place immediately after integration. I know that to my own cost because it happened with me. My father signed the integration. I was neither the ruler nor had I anything to do with it. But, when he died, somebody came up and wanted to sue me for something my father did as ruler. Naturally, the matter went up to the President and I was asked to submit what I had to say in the matter. And, I put my case and said that I was not responsible for anything and what took place was my father's responsibility as the chief executive. Naturally, the Government of India had the matter carefully examined and it was turned down.

I hold no brief for the rulers and I do not care what happens. I only wish that people should have a proper perspective and grasp as to why this was done. Sardar Patel was a great man and he was a great man who could look into the future, probably, better than we can And, he knew that these heads of States might be placed in a very awkward situation where people later on would try to victimise them and their children It would almost be tantamount to the children of a Prime Minister being victimised for any fault that he might have committed in the discharge of his duties. I do not deny that every human being is equal before law. Speaking for the younger generation I would welcome if the princes are all put on the same footing as anybody else I would also like to say this. Whatever you do, do that before, the next elections so that some men from among the princes will come and stand up for the rights of the people and represent them. By all the privileges

that you have given to the rulers I might say that you have virtually turned them into "women". I would like to see some men coming out of them who would stand up for the rights of people—just half a dozen or so—on the same principle as all my brothers here

Mr. Deputy-Speaker: Whatever that be it is a reflection against women and they may resent it, they are as strong as men in these days

Shri Karni Singhji: I do not want to use another word and that is why I have said 'women', I wanted to say something else but I thought that it would not be parliamentary

I do not care what you do about this measure but please try to understand what inspired this Government and whatever decision the nation wishes to take, let them by all means take. I do not speak for the princes at all

Mr. Deputy-Speaker: Happily there was no woman present, otherwise she would have objected to your speech!

Shri Datar: Mr Deputy-Speaker, the question raised by my hon friend the sponsor of this Bill raises certain very important questions—about its constitutionality and the propriety We have to take into account the circumstances under which certain agreements or covenants were entered into subject to which there were agreements under which we had a merger This question is, therefore to be considered in a very dispassionate way and full effect will have to be given to the sanctity of covenants that were entered into, as my hon friend just now pointed out, on behalf of the Government of India by the first Home Minister, the late Sardar Vallabhbhai Patel I shall briefly point out how the position arose in respect of the question that has been raised by my hon. friend Before the advent of Independence under the Code of Criminal Procedure, the foreign rulers as also the rulers of the Indian States were given certain exemptions or immunities Thereafter, the question arose when we had our Independence and it was taken up with the integration of the States Agreements were then entered into and those agreements may be found by the hon Members here in the white paper on Indian States published by the Government of India in the then Ministry of States One of the clauses or articles deals with this question specifically,

> "No enquiry shall be made nor any action taken by or under the authority of the United State or the Government of India and no proceedings shall lie in any court against the ruler of any covenanting State, whether in his personal capacity or otherwise in respect of anything done or purported to be done by him under his authority or during the period of his administration of that State"

This was the covenant that was entered into By reason of this covenant we granted to the rulers the continuance or the retention of the privileges that they had before the date of integration That is the reason why under these various covenants or merger agreements, the Government of India guaranteed to the rulers of the merged or integrated States privileges and dignities enjoyed by them immediately before the 15th August 1947

The next point that was referred to in this connection is with reference to articles 362 and 291 Article 291 refers only to the question of purse But so far as the covenants or others are concerned, they are governed by article 362, and we cannot put a limited interpretation on the provision of article 362 only because these covenants have been referred to in respect of one matter in article 291 That is the correct interpretation Therefore, we are governed by an article in the Constitution, and so far as these covenants or agreements are concerned they have got to be respected because it is an article in the

[Shri Datar]

Constitution the sanctity of which has to be accepted by all of us.

Shri Ajit Singh Sarhadi: Sir, the covenant which the hon. Minister has read out only pertains to protection and immunity relating to what has been done before the merger and not to subsequent commercial transactions.

Mr. Deputy-Speaker: There is another covenant saying that all privileges they had been enjoying before 1947 will be continued.

Shri M. L. Dwivedi: Privileges which they were enjoying in their discharge as rulers. But when they enter into business, not as rulers, then such things do not come into the picture.

Mr. Deputy-Speaker: The one which he read out is a different thing. There is another covenant that all their dignities and privileges that they were enjoying on that date shall be continued.

Shri M. L. Dwivedi: On that date, not afterwards. What they do over and above what they had, is not covered by the covenant.

Mr. Deputy-Speaker: Under this section which the hon. Member wants to repeal or change they had that advantage, that they were immune from any action in the civil courts.

Shri Jaipal Singh: They had business before also.

Shri Datar: May I remind my hon. friend of the phraseology in article 18 of the covenant reported in the White Paper? There it has been stated that so far as these immunities are concerned they might be in respect of any act done by him in his personal capacity or as an ex-ruler.

Shri M. L. Dwivedi: Done, not what they will do.

Shri Datar: There is no such thing as "then" or "now". Let not the hon. Member put some forced interpretation with a view to suit his own case just now.

Then, Sir, another hon. Member brought in article 14 of the Constitution, and we were told that before the law there was complete enquality in respect of all the subjects. Fortunately, this very question arose before the Bombay High Court in a case in respect of one State—I think it was Jath in Bombay State. There we have a ruling. It was in the case: The Civil Judge, Junior Division, Jath—Referror; Bhimaji Naraiu Mane—Plaintiff *versus* Vijaysinharao Ramarao Dafle, Rajesaheb of Jath.

Shri Jaipal Singh: Is it a prohibition case?

Shri Datar: No. It is not prohibition at all. It was a case where a direct point arose as to whether section 87B has been offended by article 14 of the Constitution.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Jaipal Singh smells prohibition where there is none.

Shri Datar: The word 'prohibition' might have other meanings also. We have a number of prohibitions, not merely prohibition on drinking.

Shri Jaipal Singh: Prohibition on privileges.

Shri Datar: In that particular case the plaintiff filed a suit—the case of the Civil Judge against Rajesaheb—claiming certain reliefs. A preliminary objection was taken to the maintainability of the suit in view of the provisions of section 87B of the Civil Procedure Code. The objection was that it offended a number of articles of the Constitution. I would not take the House through the long discussion, but I shall read only the last orders that have been passed in that particular case. The Judges

were Chagla, C. J. and Dixit, J. They say:

> "In our opinion, therefore, section 87B of the Code is not *ultra vires* of the Constitution and the answer we give to the question submitted to us is that the provisions of section 87B are not invalid under Article 13(2) of the Constitution."

So, that disposes of this question also.

Under the circumstances, the question that now arises is whether any person or an intending plaintiff suffers any disadvantage or is put under any handicap. May I point out that after making all these treaties, the Government of India have evolved certain principles and have now a definite policy. Before I deal with the principles, may I point out that in all cases where applications are received for permission to sue a particular ex-ruler, in my Ministry, we look into them very carefully and we consult the Ministry of Law.

Shri M. L. Dwivedi: May I point out here that permission was sought in 1954 in that Khosla case in respect of the ruler of Kapurthala, and the Ministry of Law advised that permission should be given. But still the permission has not been given. I am pointing it out to him. It is for him to look into it.

Shri Datar: Had the hon. Member pointed out any particular instance, I would have given him a clinching answer.

Shri M. L. Dwivedi: You cannot; I dare say you cannot.

Shri Datar: I have anticipated the objection. I would point out that the Law Ministry in particular took into account certain broad principles. One question is, as some hon. Members rightly pointed out, so far as these rulers are concerned, naturally they are divested of all authority, and therefore, there is a tendency—quite a natural, human tendency—to harass them and exploit them, and in some cases even to blackmail them. That has therefore to be taken into account.

Shri Panigrahi: Can you give instances where the people have harassed the rulers?

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Instances are from both sides.

Shri Datar: Let the hon. Member have the patience to hear me. We take into account whether *prima facie* the claim is justifiable or not. These questions are considered. Again, before all these questions are gone into, if the ruler has any objection or if, *prima facie*, there are any serious objections, all of them are considered by the Ministry of Law, and then we are advised as to the course of action that the Government of India should take in this respect.

May I point out here that there are certain revealing figures which would show that this matter receives the greatest and the most earnest attention at the hands of the Government of India? I am giving these figures to show that it does not mean that merely because the intending defendant is a ruler nothing should be done either against him or for him. The matter is looked into on merits and then only is a permission granted or a permission refused. Let it not be supposed that permission is refused as a matter of course.

I would give the figures relating to the period till 1957. The number of applications received from the time the Constitution came into force is 524. Out of these 524 applications, consent was given in 232 cases.

Shri M. L. Dwivedi: Only

Shri Datar: Why does the hon. Member say 'only'? Let him kindly hear me further. In 232 cases permission was granted. That means, the Government believed that it was a *prima facie* case and the plaintiff ought to be allowed to take a chance before the court of law. Then, the number of

[Shri Datar]

cases in which consent was refused was 169. That means, about one-fourth of the number of cases were settled or withdrawn. Sometimes, what happens is, after we are given notice of a suit, and after we are asked to grant permission or consent, the parties come together, and in a number of cases these matters are settled or compromised. The number of cases pending on the evening of the 14th August, 1957 was only 21. Therefore, if all these figures are taken into account, it will be found that a very searching inquiry is made, because the right to file a suit against an ex-ruler is taken away unless a permission is there. Therefore the Government are extremely anxious to see to it that no rightful claim is denied, only because the defendant happens to be an ex-ruler. The whole thing is gone into; the principles laid down are taken into account and then permission is granted. As I have pointed out, in more than half the number of cases, permission was granted and only in one-fourth of the total number of applications was permission refused. Mr. Jaipal Singh clinched the whole matter. When we have entered into certain agreements, is it proper to go back upon those agreements? It is a question of sanctity of agreements, sanctity of the various principles which have been accepted by us. Just as we have been given fundamental rights under the Constitution, similarly there are certain limitations also placed upon the equality of persons because of historical associations and because of the need for entering into such agreements at the time of merger or integration of the various States.

All the circumstances are taken into account and nothing is done with a view to see that any injustice is likely to happen. So, the Government of India are extremely anxious to see that full justice is done to all and justice also requires throwing out of applications when they have been filed for purposes other than *bona fide*.

Shri M. L. Dwivedi: Even bona fide applications have been rejected.

Shri Datar: I am not going to deal here with the question of rulers; a ruler may agree or may not agree. It is a question of the law that we ourselves have made for us. So, I request the hon. Member not to press his Bill.

The Deputy Minister of Law (Shri Hajarnavis): Mr. Deputy-Speaker, my task has been rendered very easy by my senior colleague, the Minister in the Ministry of Home Affairs. There are one or two things to which I must refer before the hon. Member who moved the Bill replies. While moving for consideration of his Bill, he said that these applications for certificate are considered in accordance not with some settled principles, but the Secretaries decide the applications on the basis of extraneous considerations. I emphatically refute the charge. What is being done is being done with our full knowledge and consent and I take the fullest responsibility for whatever decision was taken in each case.

I know it is a fact that the application after it is received is considered from every aspect and Government is anxious that no genuine grievance should go unredressed, that no person who has some sort of a case to be taken to court would be denied access to the court merely because the proposed defendant happens to be a ruler. I might add—I am sorry Mr. Jaipal Singh has just left—in doing so it is no consideration to us that the ruler belongs to this party or that party. I have an instance in my own mind where I personally dealt with a matter which related to a ruler who is an hon. Member of the other side of the House.

In these matters, as I said, there is only one consideration which impels us, *viz.*, does justice require that this case should be allowed to go to court? We only prevent a case going to court when we come to the conclusion, after anxious consideration, that it would be an abuse of the process of the court

to allow the plaintiff to file the case, that it is nothing short of blackmail The Maharaja of Bikaner has already told this House that whenever an application is made, that application is sent to the ruler against whom the suit is proposed to be filed. We get a detailed report, a detailed reply We satisfy ourselves that the reply is correct, that it is not merely an attempt to evade the possible legal responsibility—it is only then, that permission is withheld. We are as anxious, if not more anxious, as the Members of the House and other citizens of this country, to uphold the great principles of the Constitution We remember them and apply them in every case where it is our duty to apply them

Shri Dwivedi suggested that there was some sort of divergance, some sort of difference, between the approach of the Law Ministry and the Home Ministry Nothing is farther from facts

Shri M L Dwivedi: You have not seen the case

Mr. Deputy-Speaker: Order, order Let him proceed

Shri Hajarnavis: The Ministry of Law considers the legal aspect, and the Home Ministry is concerned with the other aspects But the decision is the decision of Government and we are all responsible for it. We cannot exonerate the Ministry of Law and say that the Home Ministry is guilty The decision is the decision of the Government and the Government as a whole are responsible for the decision and we take full responsibility for the decision

Sir, a suggestion was made but the implications of that suggestion, I submit, were hardly realised. It was suggested by Shri Dwivedi—and I was a little surprised to find that it met with the approval of certain other hon. Members like Shri Sinhasan Singh—that the word "Central Government" may be replaced by the word "court". Now, the implications of this proposed amendment, as I said, have not been realised Consider this a suit is to be filed against a person who is not a ruler. He straightway files a suit. The court decides whether there is a cause of action The court will decide, on evidence being led, whether the suit makes out a good claim or whether it should be rejected as the claim is fictitious Now, suppose an application for certificate to file a suit against the Ruler is made to the court. On what basis is the application going to be decided? What are the criteria given in section 87B? Will the suit be tried twice? If the claim is good, if the claim is one which ought to be allowed, then surely the moment he decides that permission ought to be given, the claim is decided Should there be a further hearing?

Shri M. L. Dwivedi: You are confusing the issue?

Shri Hajarnavis: I am clear in my mind.

Mr. Deputy-Speaker: What is being confused would be clear in the reply that Shri Dwivedi will make

Shri M. L. Dwivedi: Shri Sinhasan Singh wants to raise a point of order

Shri Sinhasan Singh: On a point of order In the pauper suit, the court grants permission to file a suit.

Mr. Deputy-Speaker: Not on the merits of the case but as regards the capacity of the plaintiff to pay the court fee That is a different thing altogether

Shri Sinhasan Singh: Here the case to be decided is whether there is a *prima facie* case or not. These are two distinct things.

Shri Hajarnavis: As I said, we try to see, as has been pointed out by the Maharaja of Bikaner and the Minister of Home Affairs, that the proposed suit is not merely an attempt to blackmail persons who were peculiarly vulnerable in a historical situation That is the only thing

[Shri Hajarnavis]

which weighs with us. After all, we cannot judge the quality of the evidence But if it appears to us that to allow this suit would be abuse of the process of law, then it becomes our duty, our responsibility according to the undertaking which has been given in the solemn document, our Constitution, to withhold permission, and Government intend to do so. That being our responsibility and we being answerable to this Parliament for a decision taken by us in that behalf, we cannot transfer our responsibility to the court. On what material will the court decide that permission ought to be given or not given, except upon the evidence that the claim is true or the claim is false? The matter to be decided by the court will be a matter dealing with the merits of the case. That being so, the proposed amendment would result in a new burden being added on the shoulders of the rulers, rather than a protection being extended to them If you allow section 87B to remain in some form, its function must be to give some protection to the ruler I submit, the proposed amendment would not only not give any protection to the ruler, but would add to the burden inasmuch as he will have to resist twice instead of once

The third point for the consideration of the House would do this. Every one knows that section 87B is a part of our law That is to say, if he enters into a contract with a ruler, he will not be able to sue him unless he obtains a certificate from the Central Government. Every one who advances money to a minor knows that if the minor does not willingly pay it back, he cannot sue

Shri M. L. Dwivedi: What about moneys given when the States were in existence and that money is not being returned?

Shri Hajarnavis: The simple answer to that question is, was a suit competent against the ruler at that time? If he was sovereign, could he be sued in his own court?

Shri M. L. Dwivedi: He would be, just as the President.

Mr. Deputy-Speaker: That was not admissible in those States. The ruler could not be sued in his own State

Shri M. L. Dwivedi: We are not in those days, we are in modern times

Shri Hajarnavis: If no liability existed before the Constitution, was it expected of the Constitution that a liability would be created where none existed?

Shri M. L. Dwivedi: It has been created

Shri Hajarnavis: It has not been created It could not be created. It has been ruled by the Supreme Court that the Constitution is not retrospective Unless express words were there in the Constitution, no liability could be created in respect of a transaction for which no liability was incurred before the Constitution. That, I understand, is the plain law Therefore, as regards this transaction which was entered into with the ruler after the Constitution came into force, it is clear that the man who enters into the transaction must know that if the matter has to go to the court, or it results in litigation, that litigation cannot be started unless the certificate of the Central Government is there The law is there for every one to read. If, knowing the law, with his eyes open, he enters into a transaction with the ruler, shall we not say that he takes all the consequences? That being the position, since it is a solemn undertaking which we have given, which we have embodied after a great deal of thought, Government are of the opinion that it should not be lightly brushed aside.

Our law is replete with many instances where people in various stations enjoy privileges. For instance, we are all aware that under the Criminal Procedure Code, no prosecution can be begun against a government servant unless the sanction of the

Central Government or the appropriate authority is obtained, for any act which is alleged to be done in the course of his official duty. Judges are exempt, and rightly so, for all that they do, while acting as Judges. They must have freedom. They must be independent. They must not be threatened with action for everything that they do acting as Judges. There are people, I submit to the House, who are protected, given special protection by our law against legal proceedings. If there are a few rulers who are enjoying this privilege by virtue of an undertaking given by the Constitution, Government intend to keep their word. That being the position, I request my hon. friend to withdraw the Bill.

17 hrs.

श्री म० ला० द्विवेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्हों ने इस विधेयक का समर्थन किया है । मुझे खेद है कि वाजपेयी साहब उस समय इस सदन में नहीं थे जब कि राज्यों का विलीनीकरण हुआ था । मुझे खेद है कि उन्हों ने उन कवेनेन्ट्स और शर्तनामों का उतना अध्ययन नहीं किया है जितना कि मैं ने किया है । मैं राज्यों के आन्दोलनों से सम्बन्धित रहा हूं और सरदार पटेल से भी मेरा निजी सम्बन्ध रहा है, और मैं उन सब बातों से भली भांति परिचित हूं । सरदार पटेल ने राजा महाराजाओं को जो अधिकार दिये हैं मैं उन का हामी हूं । मैं राजाओं का विरोधी नहीं हूं । मैं समझता हूं कि वे हमारे साथी हैं । उन्हों ने देश के लिये अपनी सत्ता दी । किन्तु उस कवेनेन्ट के बाद नई बातें पैदा हुई हैं उन बातों को भी आप सुन लें । हमारा समाज स्थिर समाज नहीं है, वह स्टैटिक नहीं है, वह रिजिड नहीं है । उस में फ्लैक्सिबिलिटी है । जब कोई नई बातें उत्पन्न होती हैं तो हमें उन के मुताबिक अपने को ढालना पड़ता है । यही कारण है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आप के विरुद्ध दिया तो आप ने एक नया कानून बना कर उस को ठीक किया । क्या सदन इस बात का गवाह नहीं है । आज स्थिति यह है हमारे राजा महाराजाओं में से ९० या ९५ प्रतिशत ऐसे अच्छे हैं कि वे अपने व्यवहार में गड़बड़ी नहीं करते, लेकिन जो ५ फी सदी हैं वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन के कारण जो निरीह जनता को नुकसान हो रहा है उस की ओर यह मंत्रालय ध्यान नहीं दे रहा है । मंत्री महोदय ने कहा कि हमारा मंत्रालय बड़े गौर से इन चीजों को देखता है । उन्हीं ने बतलाया कि ४०० और कुछ केसेज में से २३२ केसेज तै नहीं किये गये हैं यानी आधे केसेज निपटाये गये हैं । बाकी पड़े हुए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने कहा था कि २०० केसेज में तो फैसला दे दिया गया है कुछ केसेज बाकी हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं उस पर आ रहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस पर आ तो रहे थे लेकिन फैसला पहले ही दे दिया कि वे पड़े हुए हैं । उन्हों ने कहा था कि पड़े हुए नहीं हैं । बीस पच्चीस बाकी हैं । दूसरों में फैसला दे दिया गया है । या आपस में बाहमी फैसला कर लिया गया है ।

An Hon. Member: He said, in 32 cases permission has not been given.

Mr. Deputy-Speaker: There was no occasion for giving or refusing permission in certain cases because they came to a compromise. Where would be the question of refusal?

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह कह रहा था कि २३२ केसेज में इजाजत दी गई, १९९ केसेज में इजाजत नहीं दी गयी, कुछ केसों में फैसला कराया गया । फैसला कराने के ढंग के बारे में मैं ने कहा था कि कम्प्रोमाइज कराने में पार्टीज पर दबाव डाला जाता है ताकि उन को रुपया कम दिया जाये । जो डिफाल्टिंग पार्टीज हैं उन के पक्ष में या किसी प्रकार से ऐसा समझौता कराने की कोशिश की जाती है

[श्री म० ला० द्विवेदी]

कि वह बेचारा मजबूर हो जाता है और सोचता है कि जो कुछ मिल जाये वही बहुत है ।

Shri Datar: This information is absolutely wrong. Let the hon. Member be careful.

Mr. Deputy-Speaker: There would be difficulty in bringing forward any problem here, because we have to observe rules. He should have given notice beforehand. This is not a forum where we can discuss merits, saying that such and such a case should have been given permission. That would not be permitted here. This is not the forum where such matters, relating to individual cases, can be discussed.

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं मंत्री महोदय को यह किसी समय बतलाऊंगा । यह सत्य है कि भीमसेन खोसला को यह कहा गया कि तुम इस केस को कम्पाउन्ड कर लो और इतना रुपया मान लो । जो राजा महाराजा ने बात कही थी उसी को मिनिस्ट्री दुहराती थी । अफसोस है कि जो कपूरथला के राजा ने कहा वही मिनिस्ट्री कहती थी और उस आदमी को नुकसान में डालने की कोशिश की गयी । लिहाजा कम्पाउन्ड ठीक नहीं हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को मशविरा दूं कि वे किसी चीज को इस तरह से ले कर हाउस में इतने जोर से कहें यह ठीक नहीं मालूम देता ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं निष्पक्ष रूप से कह रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आया आप ही यह फैसला करेंगे कि आप निष्पक्ष रूप से कह रहे हैं । मिनिस्ट्री भी कह रही है कि हम निष्पक्ष रूप से कह रहे हैं । आप भी कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष रूप से कह रहे हैं । तो कैसे फैसला होगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं कहता हूं कि तमाम कागजात सदन पटल पर रखे जायें तो मालूम हो जायगा कि कौन सी बात ठीक है । अगर सारे कागजात पटल पर रखे जायें तो मालूम हो जायेगा कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है । अगर जैसा मैं कहता हूं वैसा न निकला तो मैं अपने शब्दों को वापस ले लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मिनिस्टर साहब के पास चले जायें और कागजात देखने के बाद निर्णय कर लें तब यहां आयें ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं कहता हूं कि कि श्री दातार साहब ने सारी बातों का अध्ययन नहीं किया है और चूंकि उन्हें उत्तर देना है इसलिये उन्होंने उत्तर दे दिया । मैंने यह नहीं कहा कि हम राजाओं के अधिकारों को छीनना चाहते हैं । हमारे मित्र सिंहासन सिंह ने भी एक सुझाव दिया । मैं ने भी कहा कि आप इस अधिकार को उदारतापूर्वक बरतें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं ने तीन सुझाव दिये उन में से उन्होंने एक को भी नहीं माना है । और सचिवालय ने उन को जो ब्रीफ दिया है उसे वे रत्ती भर भी ज्यादा नहीं डोलना चाहते । और जो निर्णय लेने वाले मंत्री हैं वे यहां हैं नहीं ।

Shri Datar: The whole thing is absolutely wrong. The insinuation is most unfair. Let the hon. Member not go on making insinuations.

श्री म० ला० द्विवेदी : श्री जैपाल सिंह जी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं । उन्होंने मेरे विधेयक का विरोध किया है । उन्होंने बतलाया है कि वे पुराने सदस्य हैं । लेकिन मैं तो उन बातों को ठीक समझा नहीं जिनकी ओर उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया । मुझे खेद है कि उन्होंने मेरा पूरा व्याख्यान नहीं सुना और बिना मेरा पूरा भाषण सुने हुए अपना भाषण दिया । अगर वह मेरा पूरा भाषण सुन लेते तो मुझे से सहमत होते । वे मेरे मित्र हैं और हर चीज को सहानुभूतिपूर्वक देखते हैं ।

उन्होंने कहा कि आदिवासियों को कुछ स्वत्व मिले हुए हैं । मुझे बड़ी खुशी है कि उनको वे स्वत्व मिले हुए है और मैं तो चाहता हूं कि आदिवासियों को और हरिजनों को अधिक से अधिक अधिकार मिलें क्योंकि वे सदियों से पिछड़े हुए और ठुकराये हुए चले आ रहे है। मैं तो चाहता हूं कि उनको बराबर अधिकार मिलें रहें जब तक कि वे हमारे बराबर न आ जावें । लेकिन राजा महाराजा तो सम्पन्न लोग हैं । उन्होंने देश के लिए अपने अधिकार छोड़े है । इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और उनके त्याग की प्रशंसा करता हू और आज वे स्वयं इस तरह के अधिकार को बरतना नही चाहते । वे तो उदारता दिखा रहे है लेकिन दूसरी तरफ मंत्रालय कवेनेन्ट्स की आड ले रहा है जिनमें रिजिडिटी है । आज हमारे समाज में स्थिरता नही है । हमारा समाज फ्लेक्सिबिल है । हमे नई आवश्यकताओ के अनुसार अपने कानून का निर्माण करना होगा, उसमे सुधार करना होगा ।

हमारे विधि उप-मन्त्री ने कहा कि केस अदालत के सामने दो बार जायेगा वह कहना गलत है । मै कहता हू कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के पहिले परमिशन लेनी पडती है फिर अपील चलती है । तो क्या इसके मानी यह हुए कि वह केस अदालत में दो बार चला । मुझे अफ़सोस है कि ला का ज्ञान रखते हुए भी वह इतनी सी साधारण बात न कह कर एक ऐसी दलील दे रहे है, जो सदन को नही जंच सकती ।

Shri Hajarnavis: May I .....

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि इस की कोई जरूरत नही है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मुझे हर्ष है कि हमारे मित्र, बीकानेर के नरेश ने, जो कि संसद् के सदस्य है, बड़े उदार विचार हमारे सम्मुख रखे हैं । उन्होंने शासक की हैसियत से नही, बल्कि जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने विचार रखे हैं । मैं उन विचारों का समर्थक हूं । मैं नही चाहता कि हमारे राजा-महाराजाओ के लिए एक दुःखद वातावरण उत्पन्न करने और उन को सताये जाने की बात कही जाये । मैं उस बात का विरोध करता हूं । मै चाहता हूं कि उन को कोई सताये नही । इस लिए मैं श्री सिंहासन सिंह के सुझाव को मानने के लिये तैयार था कि जो अधिकार गृह मंत्रालय के पास है, वह अधिकार न्यायालय को दे दिया जाय । इस वक्त गृह मंत्रालय एक ब्यूरोक्रेसी से गवर्न्ड है । ब्यूरोक्रेसी जैसा निर्णय करती है, उस को वह मान लेते है । जब हमारे न्यायालय के लोग गृह मन्त्रालय से ज्यादा योग्य है, जुडिशरी हमारे देश की निर्णायक है, तो फिर यह अधिकार क्यों न उस को दे दें कि आप निर्णय कीजिये कि अमुक मुकदमा होना चाहिए अथवा नही । अगर वह कहे कि नही होना चाहिए, तो केस को आगे न चलाया जाये और अगर कोर्ट को विश्वास हो जाय कि अमुक केस हैरासमेंट और सताने के लिए नहीं है, बल्कि वह वास्तविक केस है, तब तो वह मुकदमा चलाने की इजाजत दे दे । जुडिशरी के जरिये वह इजाजत मिलनी चाहिए । गृह मंत्रालय क्यो यह बोझा अपने ऊपर लादने के लिए तैयार है ? संविधान में कहा गया है कि इस सम्बन्ध मे सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट की जरूरत है । तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक संशोधन द्वारा कोर्ट को यह अधिकार दे सकती है । धारा ८७वी मे राजा-महाराजाओ को जो सुरक्षा मिली हुई है, वह उन को मिली रहेगी और साथ ही साथ आप जनता के प्रति भी न्याय कर सकेंगे । यह एक ऐसी उचित माग है कि अगर कोई भी समझदार व्यक्ति इस सदन मे होगा, तो वह इस को मानने के लिए तैयार होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो इस को न मानेंगे, वह गैर-समझदार है ? यह बात तो नहीं कहनी चाहिए ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मुझे अधिकार है इस बात के कहने का ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर दूसरे भी कह सकेंगे ।

श्री म० ला० द्विवेदी : कहें, उन्होंने कहा है । कुछ लोगों ने मुझ पर लांछन लगाए हैं बावजूद इस बात के कि बड़े उदार विचारों से प्रेरित हो कर मैंने इस विधेयक को सदन के सामने रखा है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिये नहीं । मेरा यह उद्देश्य है कि भारत में और हमारे समाज में न्याय की व्यवस्था कायम हो । मेरे इरादे पर शक करना एक ग़लत बात है, क्योंकि अगर मैं न्याय की व्यवस्था की स्थापना के लिए एक बात कहता हूं, तो उस की सराहना करनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इरादों पर किस ने शक किया है ?

Shri Datar: None has attributed any motives.

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरे मित्र ने कहा है कि सदस्यों के अधिकारों को ज्यादा चाहते हैं । मैं पहला आदमी हूंगा जो उनको छोड़ने के लिये तैयार हूंगा । मैं चैलेंज करता हूं कि श्री जयपाल सिंह को कि मैं पार्लियामेंट के तमाम अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार हूं वह भी आयें और छोड़ें । अधिकारों के इस्तेमाल के लिये वह आगे आ जाते हैं, लेकिन जब लांछन लगाने की बात आ जाती है, तो सदस्य सदस्यों को लांछित करते हैं । हम त्यागी लोग रहे हैं । हम देश के लिये जान कुर्बान कर सकते हैं और इस सदन के सदस्यों को जो छोटे मोटे प्रिविलेजिज मिले हुए हैं, हम उनको छोड़ सकते हैं । हम को उनका लालच नहीं है । जो चार सौ रुपए सदस्यों को मिलते हैं, हम को उनका मोह नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मगर वह तो किसी से छुड़वाने के हक में नहीं है । अब माननीय सदस्य को खत्म करना चाहिये ।

श्री म० ला० द्विवेदी : थोड़ा सा और रह गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे तो एक घंटे से ज्यादा एक्सटेंड करने का अख्तयार नहीं था । इस बिल को मैं जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सकता था, वह मैंने दे दिया ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं इस विधेयक के बारे में मैं कोई विशेष बातें नहीं कहना चाहता हूं । एक बात कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

अभी हमारे दातार ने कहा है कि केवल २१ केस ऐसे हैं, जिन में इजाजत नहीं दी गई । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर २१ केस मर्डर के केस होते और उन को पेंडिंग रखा गया होता, तो न्याय का गला घोंट दिया गया होता या नहीं । मान लिया कि सिविल सूट थे, लेकिन वे २१ केस कितने साल से पेंडिंग पड़े हैं इस का उत्तर उन्होंने नहीं दिया । मैं चाहता हूं कि मन्त्रालय इन बातों पर फिर गौर करे और जो केसेज पड़े हुए हैं, उन को शीघ्र से शीघ्र डिसपोज करे और उनका फैसला दे । साथ ही साथ जिन मामलों में अन्याय की दुहाई दी जाये, उन पर वह पुनः विचार करे । वह राजाओं से परामर्श करे और अगर वह समझौता कर सकता है, तो अच्छा है, नहीं तो मुकदमा चलाने की इजाजत दी जाये । झूठे केसिज को इजाजत न दी जाय, मैं इस को मानता हूं, लेकिन यह कहना कि हम सब बातों में बहुत केयरफुल हैं— बहुत सावधानी रखते हैं, कुछ अर्थ नहीं रखता है । मंत्री जी को मैं जानता हूं कि वह बड़े सावधान हैं, लेकिन जहां पांच सौ केसिज हों, वहां मंत्री जी का ध्यान पांच सौ केसिज की तरफ नहीं जा सकता है । जो डीफ सैक्रेटेरिएट से आता है, जिस तरह से आता है, वह आप जानते हैं । आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है । अगर यह न होता, तो ये मूंधड़ा डील और दूसरे डील न होते । अगर मंत्री जी आश्वासन दें कि वह इस बिल

पर रीजनेबल तरीके से विचार करने के लिये तैयार हैं, या इस संशोधन पर विचार करने के लिये तैयार हैं, तो मैं सदन के सामने प्रस्ताव रखता हूं कि इस विधेयक पर विचार तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाये, जब तक कि इस बारे में दूसरा विधेयक न लाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय . अब तो वह आप से आश्वासन चाहते हैं ।

श्री ब० ला० द्विवेदी : अगर वह मान लें कि आगे वह इस को मान लेंगे, तो मैं वापस लेने के लिये तैयार हूं । अगर वह अवसर चाहते हैं, तो वह हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय · तो फिर मैं हाउस के सामने रखूं ?

श्री ब० ला० द्विवेदी . माननीय मन्त्री कोई एसोरेंस दें ।

Shri Datar: I have already given my assurance. I have already said that we look very carefully into every matter.

श्री ब० ला० द्विवेदी : मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि केयरफुली देखा जाता है । इस लिये मैं चाहता हूं कि इस पर वोट हो जाये ।

Shri Jaipal Singh: Since my name has been brought into the picture, I think I have a right to explain my position.

Mr. Deputy-Speaker: It does not matter.

Shri Jaipal Singh: I am prepared to surrender every right; let him and his companions on that side surrender their rights, then I shall be the first to surrender my rights.

Mr. Deputy-Speaker: They can decide this when they go out just now.

The question is:

"That the Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908 be taken into consideration.".

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: Then, there are three Bills in the names of Shri Easwara Iyer, Shri Raghunath Singh and Shri Wadiwa respectively. The hon. Members concerned are absent. Now, Shri Jhulan Sinha.

17.13 hrs.

INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL

(Insertion of new section 99A and amendment of sections 113, 118 and First Schedule)

Shri Jhulan Sinha (Siwan): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890, be taken into consideration.".

The House knows that this Bill was introduced long before the official amendment Bill was passed by this House. This Bill was to be taken up on a previous day, but I was given to understand by those in the know of things that Government were going to cover some of the points that I had touched in my Bill, and I was, therefore not so serious in piloting this Bill further. But after the passing of the official amendment Bill, I feel that the points that I have touched in this Bill are altogether untouched by the official Bill I am, therefore, here to plead my case before this House.

The first offence that the Bill seeks to create is a new offence so far as the Indian Railways Act is concerned, and that is the offence of pilfering of goods in transit. The House knows that this offence of pilfering on the